गरवी गुजरात

PRGI No. UPHIN/25/A1697

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 076
दि. 15.07.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

तो यूक्रेन पर हो जाता परमाणु हमला, पीएम मोदी की एंट्री ने कैसे रोका महाविनाश?

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। पौलेंड के मंत्री ने 2022 की घटनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने युद्ध के दौरान रूस को टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने में अहम भूमिका निभाई थी।

पौलेंड ने रूस-यूक्रेन युद्ध को और बढ़ने से रोकने की कोशिशों में भारत की भूमिका की तारीफ की है। उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव थियोफिल बार्टोसजेव्स्की ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिसकी बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गंभीरता से सुनते हैं।

उन्होंने 2022 के आखिर की घटनाओं का भी जिक्र किया और दावा किया कि ढट मोदी ने युद्ध के दौरान रूस को टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने के लिए मनाने में भूमिका निभाई थी।

रूस के साथ भारत के दशकों पुराने रिश्ते- बार्टोसजेव्स्की

समाचार एजेंसी अठक से बात करते हुए बार्टोसजेव्स्की ने कहा कि रूस के साथ भारत के दशकों पुराने रिश्ते नई दिल्ली को एक खास स्थिति देते हैं, जिससे वह शांति की कोशिशों में एक अहम खिलाड़ी बन जाता है।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के एक बहुत जाने-माने और सम्मानित नेता हैं। भारत के रूसी फेडरेशन और उससे पहले सोवियत संघ के साथ गुटनिरपेक्ष देश के तौर पर लंबे समय से संबंध रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन असल में प्रधानमंत्री मोदी की बात पर ध्यान देते हैं।"

पोलैंड के मंत्री ने कहा कि ढट मोदी उन कुछ नेताओं में से हैं जो रूसी राष्ट्रपति पर असर डाल सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब मॉस्को से बातचीत करना मुश्किल हो गया है।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी उन कुछ लोगों में से हैं जो राष्ट्रपति पुतिन पर कुछ दबाव और असर डाल सकते हैं, और साफ तौर पर भारत इस टकराव को रोकने में मदद के लिए ऐसा कर सकता है।"

बार्टोसजेव्स्की के मुताबिक, संयम बरतने की अपील तब ज्यादा असरदार होती है जब वे ऐसे देशों की तरफ से आती हैं जिन्हें रूस दुश्मन नहीं मानता। भारत के साथ-साथ उन्होंने चीन का भी जिक्र किया, जिसकी बात मॉस्को में मायने रखती है।

उन्होंने कहा, "हर कोई तनाव बढ़ने के खिलाफ है, न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाला भारत बल्कि चीन के शी जिनपिंग भी। यह बात तब और अहम हो जाती है जब

यह उन देशों की तरफ से कही जाती है जिन्हें रूस का दुश्मन नहीं माना जाता। यहां भारत की भूमिका बहुत अहम है।"

भारत के साथ तेल को लेकर मतभेद कम हुए- पोलैंड

बार्टोसजेव्स्की ने यह भी कहा कि पोलैंड और भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चा तेल आयात करने के मुद्दे पर अपने मतभेदों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने माना कि वॉरसॉ ने पहले भारत की खरीदारी की आलोचना की थी, यह तर्क देते हुए कि इससे रूस की युद्ध-कालीन अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिल रही थी।

साथ ही, उन्होंने कहा कि पोलैंड समझता है कि भारत ने कम कीमत के बड़े फायदे के कारण तेल खरीदने का फसला क्यों किया। उनके अनुसार, अब दोनों देशों को एक-दूसरे के रुख की बेहतर समझ है और यह मुद्दा अब कोई बड़ी अड़चन नहीं है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने की आलोचना की थी। हम इसके पीछे की आर्थिक वजह समझते थे क्योंकि यह भारी छूट पर मिल रहा था - बाजार भाव से लगभग 40 प्रतिशत कम। हम यह समझते थे, लेकिन इससे रूस की युद्ध-कालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा था। इसलिए इस मामले पर हमारा नजरिया अलग था।"

पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ

ये बातें पुतिन द्वारा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ करने के कुछ हफ्ते बाद सामने आई हैं। उन्होंने कहा था कि मॉस्को के साथ नई दिल्ली के रिश्तों को लेकर पीएम मोदी पर दबाव बनाने की दूसरे देशों की कोशिशें बेकार होंगी।

रूस में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान पुतिन ने कहा, "हर कोई समझ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत - जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, पर दबाव डालना अंतरराष्ट्रीय और द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदेह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह दबाव कहां से आ रहा है। हमें कोई नकारात्मक परिणाम नहीं दिखते।"

उन्होंने आगे कहा, "हमें खुशी है कि भारत उन सभी देशों के साथ अपने संबंध विकसित कर रहा है जिन्हें वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण मानता है।"

पीएम मोदी की 'पंचायत' के अभिनेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत, पूछा- 'सुन रहा है ना बिनोद'

(जीएनएस)।

ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बनी और देश दुनिया के दर्शकों को लुभाने वाली वेब सीरीज पंचायत के कलाकारों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिट वेब सीरीज 'पंचायत' के प्रमुख किरदारों से मुलाकात की।

'सुन रहे हो बिनोद' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोकप्रिय सोशल मीडिया हैंडल 'मोदी स्टोरी' की पोस्ट में इसका जिक्र किया गया है। यह लोकप्रिय सीरीज के संवादों में से एक है, जिसे पीएम मोदी ने दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक से मुलाकात के दौरान बोला था, जिन्होंने सीरीज में भूषण/बनरकास और बिनोद के किरदार निभाए हैं। प्रधानमंत्री के

इस व्यवहार से कलाकार अभिभूत हो गए।

सोमवार को हिंदी में पोस्ट में आगे लिखा गया, 'सुन रहा है ना बिनोद' पंचायत फेम अशोक पाठक, यानी बिनोद, और दुर्गेश कुमार जब पीएम मोदी से मिले, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एंट्री लेते ही यही डायलॉग मार दिया! माहौल एक सेकंड में एकदम लाइट हो गया..

अशोक पाठक कहते हैं, 'सच में सोचा नहीं था इतनी नॉर्मल बात होगी। पीएम मोदी का 'मर और याददाश्त दोनों नेक्स्ट लेवल हैं। हम तो बस हंसते रह गए।' अंत में, उन्होंने लिखा, 'सचमुच, पीएम नरेंद्र मोदी का लोगों से जुड़ने का तरीका बेमिसाल है!' कार्यक्रम में, पीएम मोदी ने अभिनेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया और हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा, 'पंचायत सुनता है कि नहीं सुनता है?', जो कि लोकप्रिय मीम और सीरियल के डायलॉग का संदर्भ था। उन्होंने अशोक पाठक को उनके किरदार के नाम से पुकारा, जिसे अभिनेता ने अविश्वसनीय और किसी बड़े पुरस्कार मिलने जैसा अनुभव बताया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण-24 परगना जिले में नाव हादसे में हुई मौत पर दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण-24 परगना जिले में नाव हादसे में हुई मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम ने दुख की इस घड़ी में शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट किया; 'पश्चिम बंगाल के दक्षिण-24 परगना जिले में नाव हादसे में हुई मौत अत्यंत पीड़ादायक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक-संतप्त परिवारों के साथ है।

'पीएम मोदी की बात सुनते हैं पुतिन, युद्ध रुकवा सकता है भारत', पोलैंड के अधिकारी का बड़ा बयान

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। पोलैंड के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी व्लाडिस्लाव तेओफिल बाटोर्शेव्स्की ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पुतिन मोदी की बातों को गंभीरता से सुनते हैं और भारत के पास संघर्ष रोकने के लिए प्रभाव डालने की क्षमता है।

रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर पोलैंड के विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव व्लाडिस्लाव तेओफिल बाटोर्शेव्स्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में एक बहुत जाने-माने नेता हैं, जिनका काफी सम्मान किया जाता है। भारत के रूस के साथ लंबे समय से संबंध रहे हैं और इससे पहले भी एक गुटनिरपेक्ष देश के रूप में भी

उसके सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध थे।

'पीएम मोदी की बातों को ध्यान से सुनते हैं पुतिन'

उन्होंने कहा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वास्तव में उन बातों पर ध्यान देते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी उनसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन को सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से रोकने में अहम भूमिका निभाई थी।

'संघर्ष रोकने में भूमिका निभा सकता है भारत'

बाटोर्शेव्स्की ने कहा, यह सच है कि प्रधानमंत्री मोदी उन कुछ नेताओं में से एक हैं, जो वास्तव में राष्ट्रपति पुतिन पर कुछ दबाव डाल सकते हैं और अपना प्रभाव डाल सकते हैं। स्पष्ट रूप से भारत ऐसा कर सकता है और इस संघर्ष को रोकने में भूमिका निभा सकता है।

यूपी चुनाव में भाजपा पर भारी न पड़ जाए एसआईआर? 2 करोड़ वोट कटने के बाद योगी ने बदला प्लान, अब अलग लेवल की है प्लानिंग

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर विकास परियोजनाओं के जरिए माहौल बनाने में जुटे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी संगठन ने बूथ स्तर पर पूरी रणनीति बदलने का फैसला कर लिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद आई नई वोटर लिस्ट। इस प्रक्रिया में करीब 2.04 करोड़ मतदाताओं के नाम हट गए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा नाम उन जिलों में कटे हैं, जिन्हें लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। वहीं मुस्लिम बहुल जिलों में वोट कम कटे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या रक्कका असर 2027 के चुनावी समीकरण बदल सकता है। रक्कलिस्ट के बाद आने के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या यह नई वोटर लिस्ट बीजेपी का खेल बिगाड़ देगी?

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिनवा ने हाल ही में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है। 27 अक्टूबर 2025 से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हुआ था। 166 दिनों के लंबे अभियान के बाद यूपी की वोटर लिस्ट से 2 करोड़ से ज्यादा (लगभग 2.04 करोड़) वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में वोटरों का कम होना किसी भी चुनाव के नतीजों को पूरी तरह पलटने के लिए काफी है।

इस लिस्ट के आने के बाद भाजपा की परेशानियां बढ़ गई हैं। रक्कलिस्ट से सबसे बड़ा झटका सत्ताधारी बीजेपी को लग सकता है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि जिन इलाकों से सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, वे पारंपरिक रूप से बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाते रहे हैं। इसके उलट विपक्षी दलों के प्रभाव वाले या मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट कटने की दर बेहद कम रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों को बिना कुछ किए ही कई सीटों पर बढ़त मिल सकती है।

हालांकि सिर्फ वोट कटने के आंकड़ों से यह तय नहीं किया जा सकता कि किसी एक दल को सीधा फायदा या नुकसान होगा। फिर भी राजनीतिक नजरिए से देखें तो जिन इलाकों में बीजेपी लगातार मजबूत रही है, वहीं ज्यादा नाम हटने से पार्टी के सामने संगठनात्मक चुनौती बढ़ सकती है। असर इस बात पर निर्भर करेगा कि जिन मतदाताओं के नाम हटे हैं, उनमें से कितने लोग अपील या नए आवेदन के जरिए फिर सूची में जुड़ते हैं और चुनाव तक दल अपने समर्थकों को कितनी प्रभावी तरह से संगठित कर पाते हैं।

इस नई लिस्ट के आंकड़ों को देखें तो साफ हो जाता है कि बीजेपी के शहरी और गढ़ माने जाने वाले जिलों में वोटरों के नाम सबसे ज्यादा कटे हैं। लखनऊः यहां सबसे ज्यादा 9.14 लाख (22.89%) वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए।

प्रयागराजः इस जिले में 8.26 लाख (17.62%) वोटर कम हो गए।

कानपुरः यहां 6.87 लाख (19.42%) वोटरों के नाम कटे।

गाजियाबादः दिल्ली से सटे इस जिले में 5.74 लाख (20.24%) वोटरों के नाम हटे।

नोएडा और साहिबाबादः साहिबाबाद विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 30.36% और नोएडा में 23.85% वोटरों के नाम साफ हो गए।

वहीं बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे मुस्लिम आबादी वाले जिलों में वोटर कटने की दर केवल 10 से 12 फीसदी के आसपास ही रही।

ई20 पेट्रोल पर बवाल के बीच अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा लेटर, कर दी ये खास अपील

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर घमासान थमता नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। ई20 पेट्रोल को लेकर लोगों की चिंताओं पर चर्चा के लिए उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात का समय मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने ये अनुरोध किया कि पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और ई20 पेट्रोल दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं।

केजरीवाल का पीएम मोदी को लेटर

प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में अरविंद केजरीवाल ने उनसे मुलाकात का समय मांगा है। उन्होंने पत्र में कहा कि बैठक के दौरान वह ई20 पेट्रोल से जुड़े तकनीकी मुद्दों और इस विषय पर लोगों से मिली प्रतिक्रियाओं को प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहते हैं। AAP नेता ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को यह विकल्प मिलना चाहिए कि वे शुद्ध पेट्रोल या ई20 पेट्रोल में से अपनी पसंद का ईंधन खरीद सकें।

'अगर कोई व्यक्ति शुद्ध पेट्रोल लेना चाहता तो..'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध पेट्रोल लेना चाहता है तो उसे यह विकल्प मिलना चाहिए और जो लोग ई-20 पेट्रोल लेना चाहते हैं, उन्हें भी वह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। 'आप' प्रमुख ने कहा कि लोगों से बातचीत करने और ई20 पेट्रोल को लेकर उनकी चिंताओं को समझने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने ई20 पेट्रोल की कीमतें कम करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से सामान्य पेट्रोल की तुलना में माइलेज कम मिलता है, इसलिए इसकी कीमत कम होनी चाहिए।

ई20 ढी३१ङ्क' फङ्क६ः नितिन गडकरी का ई20 ढी३१ङ्क' पर खुला चैलेंज! 'इंजन खराब हुआ तो सामने आओ...'

केजरीवाल के लेटर की बड़ी बातें

केजरीवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने नागरिकों के लिए एक ऑनलाइन याचिका शुरू की है, जिसके माध्यम से लोग ई20 पेट्रोल के अपने अनुभव साझा कर सकते हैं।

उन्होंने लोगों से माइलेज में कमी और अन्य समस्याओं से जुड़ी अपनी चिंताएं साझा करने की अपील की।

उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में इस याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील करते हुए कहा कि एकत्र की गई सभी प्रतिक्रियाएं प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक के दौरान उन्हें सौंपी जाएंगी।

AAP संयोजक उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें जल्द ही मुलाकात का समय देंगे।

'आम जनता के दर्द पर कब बोलेंगे पीएम मोदी?' कांग्रेस ने केंद्र महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कह दी बड़ी बात

महंगाई के मुद्दे पर आई ताजा रिपोर्ट से सियासी घमासान तेज होने लगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर रिएक्ट करते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। यही नहीं उन्होंने पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने की अपील भी कर दी है।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता के दर्द पर कब बोलेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में दावा किया कि मोदी सरकार के 12 वर्षों का यही है असली सारः झूठे वादों की बहार और जनता पर महंगाई और बेरोजगारी का क्रूर वार। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में महंगाई ने

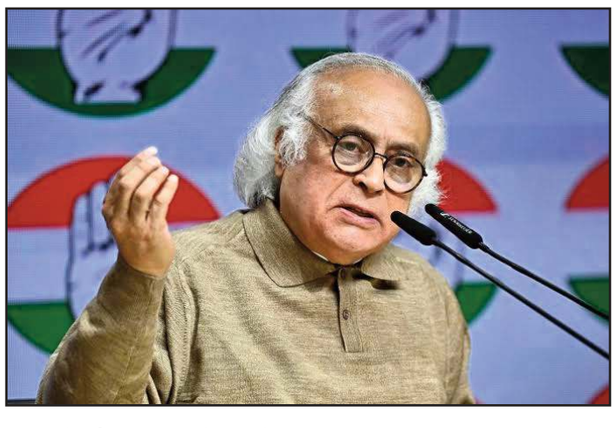

आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है।

जयराम रमेश का केंद्र पर अटैक

जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा, 'अब खुद सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं कि जून में खुदरा महंगाई 17 महीने के उच्चतम स्तर 4.38 फीसदी पर पहुंच गई है, जबकि ग्रामीण भारत में यह 4.74 फीसदी है। जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि महंगाई के साथ अब बैंकों की ब्याज दरें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे मध्यम वर्ग पर घर और गाड़ी की मासिक किस्त का बोझ भी बढ़ सकता है।

कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि मुनाफा पूंजीपतियों की जेब में और बोझ आम जनता की पीठ पर क्यों? कांग्रेस महासचिव ने यह भी प्रश्न किया कि पूंजीपतियों के संरक्षक प्रधानमंत्री मोदी आम जनता के दर्द पर कब बोलेंगे? पूंजीपतियों के संरक्षक प्रधानमंत्री मोदी आम लोगों की तकलीफों के बारे में कब बात करेंगे?

सम्पादकीय

खुफिया जानकारी के अनुसार तेहरान ट्रंप की हत्या की नई योजना बना रहा

इजरायल ने अमेरिका के साथ ऐसी नई जानकारी देने का दावा किया है, जिसमें ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अमेरिकी मीडिया में यह दावा किया गया है।

ट्रंप इस पर भड़क गए और अपना आपा खो बैठे हैं। अमेरिका का प्रतिष्ठित समाचार पत्र द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक इजरायल ने अमेरिका को बताया है कि उसके पास खुफिया रिपोर्ट है।

खुफिया जानकारी है जिसके अनुसार तेहरान ट्रंप की हत्या की नई योजना बना रहा है। मोसाद ने ये इंटेल शेयर की है और ट्रंप से कहा है कि वे ईरान के टारगेट नंबर वन पर है। इसका नतीजा यह हुआ कि नाटो के समिट के बाद ट्रंप ने डर कर अपना नया एयर फोर्स वन बदल डाला और अमेरिका से पूरा एयर फोर्स वन मंगवाया और उसमें वापस अमेरिका पहुंचे। उधर ट्रंप ने दावा किया कि अगर ईरान उनकी हत्या करने में सफल होता है तो उन्होंने पहले ही एक आदेश दे रखा है कि अगर ईरान अमेरिका पर हमला करता है, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि 1000 मिसाइलें ईरान को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या करने में सफल होता है तो उन्होंने पहले से ही एक आदेश दे रखा है। न्यूयार्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि इस आदेश के मुताबिक ईरान पर इतना बड़ा जवाबी हमला करे जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ऐसा कोई आदेश दे भी सकते हैं या फिर इतिहास में किसी नेता ने ऐसा आदेश दिया था। अमेरिकी संविधान के तहत कोई भी राष्ट्रपति ऐसा आदेश नहीं छोड़ सकता कि उसकी मौत के बाद अपने आप किसी देश पर हमला कर दिया जाए। किसी भी बड़े सैन्य अभियान का फैसला उस समय जो राष्ट्रपति होगा वही तय करेगा। क्योंकि कमांडर इन चीफ के आदेश पर ही अमेरिकी सेना ऐसा वुछ कर सकती है। ट्रंप का यह बयान सिर्प ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी जनता के लिए भी एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। एक तरफ वह अपने समर्थकों के सामने यह छवि बनाना चाहते हैं कि वह निडर हैं और सख्त नेता हैं जो किसी भी धमकी के आगे नहीं झुवेंगे, दूसरी तरफ ईरान को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो जवाब पूरे देश को मिलेगा। सभी जानते हैं कि इजरायल अमेरिका-ईरान के शांति-वार्ता से परेशान है और इसे हर हालत में तोड़ना चाहता है।

वह ट्रंप कितने बहादुर हैं यह भी जानती है। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि यह खबर चला दो कि आप ईरान के टारगेट नंबर वन हैं। इससे ट्रंप मजबूरन ईरान पर हमला कर देंगे और एक बार फिर युद्ध शुरू हो जाएगा।

हुआ भी यही। अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और ईरान ने भी जबर्दस्त जवाबी कार्रवाई कर दी। एक बार फिर मध्य-पूर्व जंग की आग में धकेल दिया गया। वैसे हम ट्रंप और नेतन्याहू से पूछना चाहते हैं कि जब आपने 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके लगभग पूरे परिवार को निशाना बनाया था, जिसमें उनकी 14 महीने की पोती भी शामिल थी, 40 से अधिक टॉप के मिलिट्री कमांडरों को निशाना बनाया था तब आपको यह ख्याल नहीं आया था कि ईरान भी ऐसा कर सकता है और अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला ले सकता है? अब जब अपने पर पड़ी तो आप को नानी याद आ गई। वैसे भी इजरायल के मंत्री ने खुलेआम ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई की हत्या करने की खुली धमकी दी थी। शहीद अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में आपने देखा होगा कि किस तरह करोड़ों लोगों ने अपने रहबर की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। ईरान आपसे बदला ले सकता है और ले भी रहा है पर इस तरह नहीं जैसे नेतन्याहू और मोसाद आपको बेववूफ बनाकर अपने हित साध रहा है।

अमेरिकी जांच के बीच भारत की पॉलिसी में बड़ा चेंज, ऐसे आयात पर लगा दी रोक

(जीएनएस)।

नई दिल्ली: भारत ने अपनी विदेश व्यापार नीति (FTP) में बदलाव किया है। मकसद यह है कि जबरन मजदूरी से बने या तैयार किए गए सामान के आयात पर रोक लगाई जा सके। यह कदम उसके व्यापार नियमों को अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप बनाता है। इससे अमेरिका की ओर से चल रही व्यापार जांच में उठाए गए मुद्दों को हल करने में मदद मिल सकती है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने FTP, 2023 में एक नया प्रावधान जोड़ा है। ऐसा करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह केंद्र सरकार को अलग-अलग नोटिफिकेशन के जरिए ऐसे सामान के आयात पर रोक लगाने का अधिकार देता है जिनके बारे में पता चलता है कि उन्हें पूरी तरह या आंशिक रूप से जबरन मजदूरी से बनाया गया है। नए नियम ऑफिशियल गजट में प्रकाशित होने के 30 दिन बाद लागू होंगे।

अमेरिकी जांच के बीच उठाया गया कदम

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत उन कई देशों में शामिल है जिन पर अमेरिका 12.5% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है।

अमेरिका यह जांच कर रहा है कि क्या उसके व्यापारिक साझेदारों के पास जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय हैं।

अभी अमेरिका को होने वाले ज्यादातर भारतीय निर्यात पर 10% टैरिफ लगता है। जबकि वॉशिंगटन

अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता से जुड़ी अलग-अलग जांच भी कर रहा है।

नए जोड़े गए पैराग्राफ 2.20इ के तहत जबरन मजदूरी का इस्तेमाल करके पूरी तरह या आंशिक रूप से बनाए गए सामान के आयात पर रोक है। केंद्र सरकार जांच के नतीजों या अपनी समझ से उचित अन्य जानकारी के आधार पर आयात प्रतिबंधों के लिए खास सामान की पहचान कर सकती है।

जोड़ी गई है नई परिभाषा

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि DGFT इस बात की जांच करेगा कि क्या आयातित सामान जबरन मजदूरी से बनाया गया था। अगर सबूत मिलते हैं तो वह सरकार से उन उत्पादों के आयात पर रोक लगाने की सिफारिश कर सकता है। जांच की प्रक्रिया 'हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, 2023' में बताई गई प्रक्रियाओं के अनुसार होगी।

नोटिफिकेशन में एफटीपी के चैप्टर 11 के तहत 'जबरन मजदूरी' की एक नई परिभाषा भी जोड़ी गई है। इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) के 'फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, 1930 (नंबर 29)' में दी गई परिभाषा को अपनाया गया है।

जबरन मजदूरी का मतलब क्या है?

नोटिफिकेशन के अनुसार, जबरन मजदूरी का मतलब है -'कोई भी ऐसा काम या सेवा जो किसी व्यक्ति से किसी सजा के डर से जबरदस्ती कराई जाए और जिसके लिए उस व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपनी सहमति न दी हो।'

DGFT ने कहा कि ये बदलाव भारत के व्यापार नीति ढांचे को मजबूत करते हैं। इससे सरकार जबरन मजदूरी से जुड़े आयात पर रोक लगा सकती है। साथ ही FTP को क्छड कन्वेंशन के अनुरूप बना सकती है। यह नोटिफिकेशन वाणिज्य और उद्योग मंत्री की मंजूरी से 'विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992' के तहत जारी किया गया था।

सिंधु जल समझौता: भारत के कड़े तेवरों से पाकिस्तान में खलबली, पानी की जंग का अतीत; वर्तमान और भविष्य क्या?

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। कई दशकों तक भारत की उदारता का पानी पीने और उसी पानी के दम पर आतंकवाद की फसल उगाने वाले पाकिस्तान के पापों का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। भारत के कड़े तेवरों और सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालने के फैसले ने कंगाल और नापाक पड़ोसी पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी है।

इस बात को ऐसे समझिए कि कभी पानी के सहारे हेकड़ी दिखाने वाला इस्लामाबाद आज बूंद-बूंद पानी और पाई-पाई के लिए तड़पने को मजबूर है। 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते' की नीति के तहत भारत ने जो रणनीतिक चक्रव्यूह रचा है, उसने पाकिस्तान को अपनी बदहाली और बेबसी पर आंसू बहाने को मजबूर कर दिया है।

ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि भारत का इस कड़े रुख से सिंधु जल समझौते का अतीत, वर्तमान और भविष्य क्या और कैसा होगा? आइए हम आपको बताते हैं।

पहले सिंधु जल समझौते के वर्तमान को समझते हैं

बात वर्तमान की करें तो पिछले छह दशकों से जिस सिंधु जल समझौते को दुनिया की सबसे सफल राजनयिक जीतों में गिना जाता था, आज वह इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यह वही समझौता है जो भारत-पाकिस्तान के बीच कई युद्धों, आतंकी हमलों और दशकों की कड़वाहट के बाद भी कभी नहीं टूटा। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है।

इसका बड़ा कारण अप्रैल 2025 में हुआ पहलगाम आतंकी हमला है। इसके बाद भारत ने सख्त एक्शन लेते हुए इस समझौते को स्थगित कर दिया है। साफ शब्दों में कहे तो नई दिल्ली ने आतंकियों के पनाहगाह पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने और पानी को एक 'रणनीतिक हथियार' के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी तेज कर दी।

इस बार पाकिस्तान की किरकिरी क्यों हो रही है?

इस बात को ऐसे समझिए कि पाकिस्तान हमेशा से भारत के पानी पर मौज करता आया है, लेकिन अब भारत ने जमीनी स्तर पर गेम बदल दिया है। इसी कारण पहले से कंगाल पाकिस्तान अब बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहा है। खैर, नापाक पड़ोसी के चिंता का विषय केवल यही नहीं है।

इसके अलावा पाकिस्तान की चिंता का विषय चेनाब-ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट भी है। इसको ऐसे समझिए कि भारत हिमाचल प्रदेश में 8.7 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाने जा रहा है। इसके जरिए चेनाब की सहायक नदी 'चंद्र नदी' के पानी को मोड़कर ब्यास बेसिन में लाया जाएगा। यानी जो पानी बहकर पाकिस्तान जाता था, उसे भारत अपने इस्तेमाल में लेगा।

पश्चिमी नदियों पर ताबड़तोड़ प्रोजेक्ट्स

भारत ने सिंधु, झेलम और चेनाब (पश्चिमी नदियां) पर जलविद्युत और सिंचाई परियोजनाओं को युद्धस्तर पर तेज कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान ने जब इस पर आपत्ति जताई और मध्यस्थता अदालत से भारत के खिलाफ फैसले दिलवाए, तो भारत ने साफ कह दिया कि हम ऐसी किसी 'गैर-कानूनी' अदालत को नहीं मानते। फलस्वरूप पाकिस्तान रोता रह गया और भारत अपने काम में लगा रहा।

इतिहास की वो 'उदारता'

अच्छा, अब इस बात को समझने के लिए भारत का यह कदम कितना बड़ा है, हमें 1947 के दौर में जाना होगा और इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। शुरूआत से समझाएं तो जब भारत और पाकिस्तान बंटा, तो नहरों को नियंत्रित करने वाले हेडवर्क्स भारत में रह गए, जबकि लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन और नहरों का जाल पाकिस्तान में चला गया।

इसके बाद अप्रैल 1948 में जब अस्थायी समझौता खत्म हुआ, तो पूर्वी पंजाब सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया। पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। हालांकि, तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद पानी बहाल कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को समझ आ गया कि उसकी लाइफलाइन भारत के हाथ में है।

9 साल की बातचीत और 'एकतरफा' समझौता

इसके बाद आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए।

कैसा था यह अजीबोगरीब समझौता?

नदी का प्रकार नदियां पानी का हिस्सा (वार्षिक) भारत का नियंत्रण पाकिस्तान का नियंत्रण

पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज लगभग 33 MAF (20%) पूर्ण अधिकार (भारत अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है) कोई अधिकार नहीं

पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब लगभग 135 टअऋ (80%) सीमित अधिकार (केवल घरेलू उपयोग, बिजली और सीमित सिंचाई) मुख्य अधिकार (बिना रोक-टोक इस्तेमाल)

इस समझौते की अजीब बात पर रौशनी डालें तो भारत ने न केवल पाकिस्तान को 80% पानी दे दिया, बल्कि पाकिस्तान में नहरें और बुनियादी ढांचा बनाने के लिए अपनी जेब से 6.2 करोड़ पाउंड (जो कि वर्तमान समय के अनुसार 79.47 करोड़ से 79.80 करोड़ रुपये) भी दिए। यह समझौता इसलिएअ भी अजीब था, क्योंकि वैश्विक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऊपर बसा देश नीचे वाले देश को पानी भी दे और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पैसे भी दे।

'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते' की नीति

ध्यान देने वाली बात यह है कि दशकों तक भारत ने इस असमान समझौते को निभाया। कारगिल युद्ध और मुंबई हमलों के बाद भी भारत ने पानी नहीं रोका। लेकिन आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के लिए भारत का सब्र अब टूट चुका है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया कि अब पानी को राजनीति से अलग नहीं रखा जाएगा। भारत ने समझौते को 'ठंडे बस्ते' में डाल दिया।

अदालती जंग में भी पाकिस्तान पस्त

पाकिस्तान ने इस मामले को लेकर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का दरवाजा खटखटाया। मई 2026 में इस अदालत ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला देने की कोशिश की, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया कि हम इस एकतरफा फैसले को कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं।

गौतम गंभीर और अजीत अगरकर में टकराव? सरेआम सामने आकर दिनेश कार्तिक ने किया बड़ा खुलासा

(जीएनएस)।

इंग्लैंड और आयरलैंड में टीम इंडिया की टी20 सीरीज में हार के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिनेश कार्तिक ने एक ऐसा बयान दिया है, जो भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला सकता है। कार्तिक ने कोच गौतम गंभीर और चीफ सलेक्टर अजीत अगरकर के बीच टकराव की बात कही है।

स्काई स्पोर्ट्स के पॉडकास्ट पर बात करते हुए दिनेश कार्तिक ने कहा कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की सोच अलग-अलग है। दोनों के बीच कुछ खींचतान है। अगरकर एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं, जिसे लेकर लंबे समय की प्लानिंग की जा सके।

दिनेश कार्तिक का तगड़ा खुलासा

कार्तिक ने कहा कि गौतम गंभीर के साथ ऐसा नहीं है, वह अपना नाम

खराब होने से भी बचना चाहते हैं। गौतम गंभीर चाहते हैं कि वह हर सीरीज में जीत दर्ज करने वाली टीम बनाएं। कार्तिक ने कहा कि कोच गौतम गंभीर का मानना है कि टीम की हार होने पर कप्तान के अलावा कोच का नाम भी खराब होता है।

कार्तिक ने कहा कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ को देखा जाए, वहां कितने प्लेयर हैं। अगर कोई खिलाड़ी दो गेम खराब खेलता है, तो वह सोचता है कि मुझे कोई रिप्लेस कर देगा। इसके बावजूद यह (आयरलैंड, इंग्लैंड रिजल्ट) होता है। यह निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति है, जिसके बारे में भारत को अब सोचना पड़ेगा और जल्दी चीजों को ठीक भी करना पड़ेगा।

इंग्लैंड में फेल हुए सभी कॉम्बिनेशन

गौरतलब है कि आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों में भारतीय टीम बैटिंग और गेंदबाजी दोनों में फ्लॉप रही। ऐसा नहीं है कि टीम में जीत दिलाने वाले खिलाड़ी नहीं थे। वहां की कंडीशंस में भारतीय टीम के प्लेयर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

5 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी तीन मैचों में मौका दिया गया था लेकिन वह भी रन बनाने में नाकाम रहे। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने रन बनाए थे। अन्य सभी प्लेयर्स फ्लॉप हो गए लेकिन यही खिलाड़ी आईपीएल में स्टार थे। इसके बाद से गौतम गंभीर, अजीत अगरकर सभी आलोचकों के निशाने पर हैं।

सड़क पर लाचार होकर भटक रहीं ये फेमस एक्ट्रेस, बिना पैसों के मां-बेटी की हुई ऐसी हालत, बेबसी देख लोग हुए परेशान

(जीएनएस)।

तेलुगू फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस पावला श्यामला पिछले तीन दशकों से लोगों को एंटरटेन कर रही हैं। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम किया है और लोगों ने उनकी एक्टिंग की हमेशा तारीफ भी की है। फिलहाल वह गंभीर रूप से बीमार हैं और पैसों की कमी से भी परेशान हैं। आर्थिक तंगी के चलते वह एक लाचार औरत की तरह सड़कों पर भटक रही हैं।

पावला श्यामला क्यों दर-दर भटक रही हैं?

आपको बता दें कि पावला श्यामला ने सिल्वर स्क्रीन पर एक मां, सास और पड़ोसी के रूप में अपनी नैचुरल एक्टिंग से लोगों के दिल में जगह बनाई है लेकिन अब उनकी निजी जिंदगी की हालत खराब हो गई है। उनके पास न तो पैसे हैं और न ही कोई काम। आर्थिक तंगी के अलावा वह गंभीर शारीरिक समस्याओं से भी जूझ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं एक्ट्रेस की बेटी की हालत भी काफी चिंताजनक है।

गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं पावला और उनकी बेटी

जानकारी के अनुसार एक्ट्रेस पावला श्यामला को 'मां' एसोसिएशन के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सेलेब्स और डोनर पहले ही फाइनेंशियली सपोर्ट कर चुके हैं। फिल्म सोर्स के मुताबिक सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने भी एक्ट्रेस ते मेडिकल खर्च और रोजाना की जरूरतों के लिए हर महीने 10,000 रुपये देने का इंतजाम किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक्ट्रेस पावला अपने ट्रीटमेंट के लिए अस्पाल पहुंची थीं लेकिन मेडिकल खर्च के लिए पैसे न होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा था।

अनजान लोगों ने पावला को पहुंचाया अस्पताल

-वहीं कार ड्राइवर ने पावला को बीच सड़क पर ही छोड़ दिया था। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने एक्ट्रेस को सड़क पर अनाथ समझकर एक चैरिटी को सौंप दिया था।

अब एक बार फिर कुछ अनजान लोगों ने हैदराबाद के एर्रागड्डा में गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल के कैंपस में पावला श्यामला और उनकी बेटी माधवी को छोड़ दिया है। हॉस्पिटल के स्टाफ ने जब उन्हें बेबस हालत में देखा, तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई।

पीएम मोदी जनता की बात सुनें', वांगचुक बोले-डॉक्टर-इंजीनियर भी नकल से बनेंगे तो देश कैसे बढ़ेगा?

जंतर-मंतर पर नीट-यूजी पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने परीक्षा सुधार, संसद में चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी से जनता की आवाज सुनने की अपील की।

(जीएनएस)।

जंतर मंतर पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह प्रदर्शन नीट- यूजी के प्रश्न पत्रों के लीक होने के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा है। इस प्रदर्शन में कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हैं। वह 17 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं।

इस बीच इंडियन एक्सप्रेस हिंदी से बात करते हुए वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता की आवाज सुनने का आग्रह किया। इसके साथ ही सभी दलों के नेताओं से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।

सवालः परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए क्या किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे से यह समस्या हल हो जाएगी?

जवाबः बिलकुल नहीं, लेकिन इससे जवाबदेही का रास्ता जरूर खुलेगा। जब तक सरकार जवाबदेही तय नहीं करती, इस तरह की मनमानी चलती रहेगी। यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज पर कलंक है। अगर परीक्षा का पेपर लीक हो जाए तो आपको किस तरह का डॉक्टर मिलेगा? ऐसे डॉक्टर आपके बच्चों का इलाज करेंगे। नकल करके पास हुए इंजीनियर आपकी इमारतें बनाएंगे, जो ढह जाएंगी और जानें जाएंगी।

सबसे अहम बात यह है कि आज देश में ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं है। सब कुछ बेईमानी पर चलता है। परीक्षा के प्रश्नपत्रों से लेकर वोटों तक, सब कुछ बिकता है। इस तरह कोई देश प्रगति कैसे कर सकता है? विकसित राष्ट्र बनने की बात तो दूर, हम इस वैश्विक गांव का सामना कैसे कर पाएंगे?

सवालः आज आपकी भूख हड़ताल का 16वां दिन है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने आपसे कोई संपर्क किया है?

जवाबः नहीं। इसलिए, अब हमारा प्रयास है कि हम अपनी आवाज को और बुलंद करें ताकि वह उन तक पहुंच सके। अगर वह उन तक नहीं पहुंची है, तो यह केवल सरकार की गलती नहीं है, बल्कि इस देश की जनता की भी गलती है जिन्होंने इसे इतना बुलंद करने में मदद नहीं की कि इसे एक गंभीर मुद्दा माना जा सके। क्या आप तब तक अपनी आवाज नहीं उठाएंगे जब तक आप अकेले न हों और आपके साथ कोई न हो? अगर जनता सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाएगी, तो सरकार के पास इसे सुलझाने के लिए बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

'शोएब अख्तर-आसिफ भारत ड्रग्स लेकर आते थे',कौन हैं आरवीएस मणि? बोले- वूल्मर भी तस्करी के चलते मरा

(जीएनएस)।

पाकिस्तानी क्रिकेटरों को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पूर्व सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसने न्यूज रूम से लेकर सोशल मीडिया तक पर सनसनी पैदा कर दी है। अठकके पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि 'पाकिस्तान के कुछ लोकोप्रिय क्रिकेटर जब इंडिया खेलने आते थे तो वो अपने साथ ड्रग्स लेकर आते थे, उन्होंने बकायदा इस मामले में शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का नाम लिया।'

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 'पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ जैसे खिलाड़ी हर दौरे पर भारत में ड्रग्स की तस्करी करते थे। एक मामले में, वे घबरा गए और उन्होंने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था।'

'उनके कोच बॉब वूल्मर, जिन्होंने इस तस्करी का खुलासा किया था, इसलिए ही मारे गए थे। 30% आतंकी हमलों के लिए इसी ड्रग मनी से ही फंडिंग की गई थी और इन सबके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था।'

'शोएब-आसिफ ड्रग्स लेकर आते थे', आरवीएस मणि का खुलासा

स्मिता प्रकाश को दिए इंटरव्यू में आरवीएस मणि ने खुले तौर पर कहा कि 'पाकिस्तान हाई कमिश्नर के सामने शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ दोनों ने अपना जुर्म कबूला था और कहा था कि वो ड्रग्स लेकर आए हैं, उनके इस कबूलनामे के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया था।'

शोएब-आमिर खुद करते थे ड्रग्स का इस्तेमाल?

जब स्मिता प्रकाश ने पूछा कि शोएब-आमिर ने तो कहा था कि ये उनके निजी प्रयोग के लिए है? तो इस पर आरवीएस मणि ने कहा कि 'ये सारी कोरी बातें हैं, वो ड्रग्स की तस्करी करते थे और वहीं नहीं जब पाकिस्तान का कोई प्रतिनिधिमंडल, क्रिकेट टीम या और भी कोई इंडिया आता था तो ड्रग्स की तस्करी होती थी।'

बॉब वूल्मर की मौत भी ड्रग्स के चलते ही हुई: आरवीएस मणि

'इस बात का विरोध पाकिस्तान टीम के इंग्लिश कोच बॉब वूल्मर ने किया था और इसी के चलते उनकी मौत हुई थी हालांकि बॉब वूल्मर की मौत की जांच कई जांच एजेसिंयों ने की थी लेकिन आज तक किसी भी रिपोर्ट में इस तरह की बातें सामने नहीं आई हैं। उन्होंने दावा किया कि आतंकवाद की फंडिंग भी ड्रग्स तस्करी से ही है।'

कौन हैं आरवीएस मणि?

आपको बता दें कि आरवीएस मणि का पूरा नाम रामास्वामी वेंकटा सुब्रा मणि है। 29 अक्टूबर 1959 को जन्मे आरवीएस मणि पूर्व सिविल सेवक, लेखक और विजिटिंग प्रोफेसर हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस के सदस्य के तौर पर, उन्होंने गृह मंत्रालय (MHA) के आंतरिक सुरक्षा विभाग में अंडर सेक्रेटरी और बाद में कपड़ा मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी (वित्त) के रूप में काम किया है।

इशरत जहां एनकाउंटर मामले में किया था बड़ा खुलासा

उन्हें मुख्य रूप से 2004 के इशरत जहां एनकाउंटर मामले में व्हिसलब्लोअर के तौर पर जाना जाता है। वे वही अधिकारी थे जिन्होंने इस मामले में 6 अगस्त 2009 और 30 सितंबर 2009 को दाखिल दो हलफनामों पर हस्ताक्षर किए थे। पहले हलफनामे में कहा गया था कि 'मारे गए चारों लोग आतंकवादी थे', जबकि दूसरे हलफनामे में इसके उलट बात कही गई और साफ सबूतों की कमी की ओर इशारा किया गया।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

'जहां ठाकुर-पंडितों की बस्ती, वहां सड़क सुविधा; दलित-पिछड़ों की बस्ती बदहाल', सपा सांसद एसपी सिंह पटेल का बयान

(जीएनएस)।

प्रतापगढ़ः समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रतापगढ़ सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सांसद यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि "जहां ठाकुर और पंडितों की बस्ती है, वहां सड़क बनी हुई है, लेकिन जहां दलित और पिछड़े समाज की बस्ती है, वहां आज तक सड़क नहीं बनी है।" उनके इस बयान को लेकर जिले की राजनीति गरमा गई है। सोशल मीडिया पर भी पक्ष और विपक्ष में लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

सांसद ने लोकसभा क्षेत्र के दौरे का किया जिक्र

वायरल वीडियो में एसपी सिंह पटेल दावा करते हैं कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र की पांचों विधानसभा सीटों का दौरा किया। इस दौरान उन्हें अधिकांश स्थानों पर यही स्थिति देखने को मिली कि दलित और पिछड़े समाज की बस्तियों में सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

उन्होंने कहा कि अब उनकी प्राथमिकता ऐसी बस्तियों में सड़क निर्माण कराना होगी, ताकि विकास का

लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंच सके।

बीजेपी ने साधा निशाना

सांसद के वायरल वीडियो पर भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा के मीडिया प्रभारी राघवेंद्र शुक्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास कार्य जाति विशेष को ध्यान में रखकर किए जाते थे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति पर काम कर रही है और बिना किसी भेदभाव के प्रदेश में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर बंटी राय

सांसद के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। एक वर्ग का कहना है कि सांसद वंचित और पिछड़े इलाकों के विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए उनके बयान को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि एक सांसद पूरे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सार्वजनिक मंच से इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। फिलहाल यह वीडियो प्रतापगढ़ की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

कौन हैं एसपी सिंह पटेल?

डॉ. एसपी सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वे लगातार दो बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य रह चुके हैं। उनका पहला कार्यकाल 5 मई 2002 से 4 मई 2008 और दूसरा कार्यकाल 5 मई 2008 से 4 मई 2014 तक रहा।

इसके बाद वर्ष 2014 से 2020 तक उनकी पत्नी कांति सिंह उसी सीट से विधान परिषद सदस्य रहीं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एसपी सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रतापगढ़ से सांसद निर्वाचित हुए।

शाह-योगी की दिल्ली में मुलाकात के मायने, क्या अयोध्या कांड के बाद तैयार हुआ 'मिशन 2027' का प्लान!

उत्तर प्रदेश में साल 2027 के महामुकाबले से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया है. माना जा रहा है कि अयोध्या में 'चंदा चोरी कांड' के बाद हालिया यूपी कैबिनेट विस्तार और अखिलेश यादव के 'पीडीए पॉलिटिक्स' को लेकर चर्चा हुई होगी. साथ ही यूपी चुनाव 2027 को लेकर एक आक्रामक मेगा प्लान तैयार किया गया होगा.

(जीएनएस)।

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी घेराबंदी शुरू कर दी है. पिछले लोकसभा चुनाव में अयोध्या समेत यूपी के कुछ हिस्सों में लगे राजनीतिक झटके के बाद, भाजपा आलाकमान फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है. इसी सिलसिले में देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मंगलवार को कर्तव्य भवन दिल्ली में हुई एक बेहद महत्वपूर्ण और लंबी बैठक ने देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है. यह मुलाकात महज एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि यह दिल्ली और लखनऊ के बीच उस 'पावर ट्यूनिंग'

का हिस्सा है, जो 2027 में विपक्ष के तमाम समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए बुनी गई है.

लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में भाजपा की उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए थे, जिसे राजनीतिक हलकों में एक बड़ा सबक माना गया. इसके बाद विपक्ष लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. लेकिन शाह-योगी की इस ताजा बैठक ने उन सभी अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है.

योगी-शाह की मुलाकात के क्या हैं मायने

इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व पूरी तरह से एक मेज पर है. पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और अमित शाह के साथ हुई इन बैठकों के बाद यह बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है कि साल 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उनके काम के दम पर ही लड़ा जाएगा.

क्या है यूपी चुनाव 2027 के लिए बना नया प्लान?

सूत्रों के मुताबिक, इस सीक्रेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश को लेकर एक 'त्रिस्तरीय मेगा प्लान' तैयार किया गया है. हाल ही में हुए यूपी कैबिनेट विस्तार के बाद शाह ने सीएम योगी को पूरी तरह 'फ्री हैंड' दिया है. सपा के 'पीडीए' पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कार्ड को काटने के लिए भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडेय जैसे हेवीवेट नेताओं और गैर-यादव ओबीसी व दलित चेहरों को जमीन पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है. अयोध्या समेत पूरे सूबे में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय से पहले पूरा करना और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति को और आक्रामक बनाया रहा है.

दिल्ली में बैठस से तय हो गया लखनऊ का रास्ता

इस बैठक के ठीक बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक बुलाई गई, जो यह दशार्ती है कि दिल्ली में जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था, उसे जमीन पर उतारने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया है. अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश देश की सत्ता का मुख्य रास्ता है, इसलिए 2027 में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

अयोध्या के नतीजों से जो डैमेज हुआ था, भाजपा उसे एक बड़े अवसर में बदलने जा रही है. अमित शाह की संगठनात्मक क्षमता और सीएम योगी आदित्यनाथ की बेदाग व सख्त छवि का यह कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन के लिए एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार कर रहा है. विपक्ष जहां अभी सीट शेयरिंग और अंदरूनी खींचतान में उलझा है, वहीं भाजपा ने 2027 के लिए अपने सबसे बड़े सूरमाओं को मैदान में उतारकर शंखनाद कर दिया है.

लखनऊ-सीतापुर फोरलेन हाईवे होगा सिक्स लेन; 1000 करोड़ की लागत, 1 घंटे में पूरा होगा सफर

(जीएनएस)।

लखनऊः लखनऊ से सीतापुर तक की फोरलेन सड़क अब सिक्स लेन चौड़ी होगी. यह बख्शी का तालाब में आउटर रिंग रोड मोड़ से सिक्स लेन चौड़ाई शुरू हो जाएगी जो सीतापुर रोड पर टोल रोड समाप्त होने तक सिक्स लेन रहेगी.

फिलहाल लखनऊ से सीतापुर तक का सफर 2 घंटे का है, जो कि सिक्स लेन रोड होने के बाद 1 घंटे का रह जाएगा. अगले 3 महीने में सीतापुर रोड को सिक्स लेन करने का काम शुरू हो जाएगा और लगभग 1000 करोड़ रुपये का खर्च इस पर होने की संभावना है.

3 महीने में शुरू होगा निमार्णः महज डेढ़ साल में इस सिक्स लेन का काम पूरा कर लिया जाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को इस सड़क के चौड़ीकरण की घोषणा की थी. जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि व सेवानिवृत आईएएस अधिकारी

दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि जहां आउटर रिंग रोड सीतापुर रोड पर उतर रही है, यानी बक्शी का तालाब में एसआरजी इंजीनियरिंग कॉलेज के मोड़ पर, वहां से फोरलेन सड़क सिक्स लेन की जाएगी. यह चौड़ीकरण सीतापुर में टोल रोड की समाप्ति तक जारी रहेगा. लाखों लोगों को तोहफा;

नैमिषारण्य धाम की राह भी होगी आसान

NHAI करेगा निर्माण, नहीं बढ़ेगा टोल टैक्सः दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि लंबे समय से सीतापुर रोड के चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी, जिसको केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका निर्माण करेगा. सड़क के दोनों ओर एक-एक लेन का चौड़ीकरण किया जाएगा. इसके साथ ही स्थानीय यातायात के लिए बेहतर सर्विस रोड भी बनाई जाएगी.

नैमिषारण्य धाम जाना होगा आसानः उन्होंने बताया कि सीतापुर तक का सफर आसान होगा और मात्र 1 घंटे में पूरा किया जाएगा. इस अतिरिक्त लेन की बढ़ोतरी के बावजूद आम जनता पर बोझ नहीं डाला जाएगा और टोल टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि लखनऊ-सीतापुर के बीच में इटौंजा, सिधौली, लहरपुर और खैराबाद आदि इलाकों को इससे बहुत लाभ होगा. इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रसिद्ध नैमिषारण्य धाम जाना भी बेहद आसान हो जाएगा. उन्होंने बताया कि अगले डेढ़ साल में इसका निर्माण पूरा हो जाने की पूरी संभावना है.

कोई 140, कोई 180... पहले ही दिन कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिखा रफ्तार का खेल, सड़क बना स्पीड टेस्ट ट्रैक

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की शुरूआत हो चुकी है. लोकल-18 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची और एक्सप्रेसवे पर सफर किया, तो वहां कई वाहन निर्धारित गति सीमा से कहीं ज्यादा रफ्तार में दौड़ते नजर आए.

(जीएनएस)।

कानपुरः कानपुर और लखनऊ के बीच सफर को आसान और तेज बनाने वाला कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे सोमवार से आम लोगों के लिए खोल दिया गया. पहले ही दिन इस एक्सप्रेसवे पर लोगों का उत्साह साफ दिखाई दिया, लेकिन कई वाहन चालकों ने इस उत्साह को रफ्तार के खेल में बदल दिया. लोकल-18 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची और एक्सप्रेसवे पर सफर किया, तो वहां कई वाहन निर्धारित गति सीमा से कहीं ज्यादा रफ्तार में दौड़ते नजर आए.

कई वाहन निकले बहुत आगे

एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान हमारी गाड़ी की औसत रफ्तार करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो तय गति सीमा के भीतर थी. सड़क बेहद शानदार और सफर काफी स्मूथ था. लेकिन इसी दौरान कई वाहन चालक अपनी कारों को तेज रफ्तार में दौड़ाते दिखाई दिए. ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों के लिए यह एक्सप्रेसवे नहीं, बल्कि

स्पीड टेस्ट ट्रैक बन गया हो.

कोई 140, तो कोई 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार

ग्राउंड पर मौजूद रहने के दौरान जब मोबाइल एप्स और स्पीड ट्रैकिंग के जरिए आसपास चल रहे वाहनों की गति देखी गई, तो कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. कुछ कारें 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थीं. कई वाहन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर दिखाई दिए, जबकि कुछ गाड़ियां 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ चुकी थीं.

इतना ही नहीं, कई ट्रक और अन्य कमर्शियल वाहन भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति में चलते दिखाई दिए. विशेषज्ञों का मानना है कि एक्सप्रेसवे की चौड़ी और बेहतर सड़कें अक्सर वाहन चालकों को तेज रफ्तार के लिए आकर्षित करती हैं, लेकिन यही तेज रफ्तार हादसों की सबसे बड़ी वजह भी बनती है. कुछ मिनट जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी कई बार जिंदगी भर का नुकसान बन जाती है.

आखिर एक्सप्रेसवे पर कितनी है तय गति सीमा?

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों जैसे कार और एसयूवी के लिए अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. वहीं कमर्शियल और भारी वाहनों के लिए यह सीमा 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. इसके बावजूद पहले ही दिन कई वाहन चालक तय सीमा से काफी ऊपर गाड़ियां दौड़ाते नजर आए. एक्सप्रेसवे पर लगे एआई कैमरे और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली ऐसे वाहनों पर लगातार नजर रख रही है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है.

क्या बाइक, ई-रिक्शा और ऑटो नहीं चल सकेंगे?

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. इसका मतलब है कि बाइक, स्कूटी, ई-रिक्शा, ऑटो, साइकिल और अन्य धीमी गति वाले वाहन इस एक्सप्रेसवे पर सफर नहीं कर सकेंगे. इन वाहनों को पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य वैकल्पिक मार्गों का ही इस्तेमाल करना होगा.

यह फैसला तेज रफ्तार वाहनों के बीच छोटे और धीमे वाहनों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है. कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे ने दोनों शहरों के बीच दूरी जरूर कम कर दी है, लेकिन इस नई सड़क पर सुरक्षित सफर की जिम्मेदारी अब वाहन चालकों की भी है. अगर रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो यह एक्सप्रेसवे सुविधा के साथ-साथ खतरे का कारण भी बन सकता है.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक मेट्रो का विस्तार, गोमती के किनारे स्पोर्ट्स सिटी; योजना के बारे में जानिए

लखनऊ मेट्रो के विस्तार की परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है। सरकार की ओर से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी।

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी में मेट्रो विस्तार की परियोजना पर विचार किया जा रहा है। इस क्रम में राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक मेट्रो विस्तार की योजना तैयार की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया था। इस स्थल तक अब लोग मेट्रो से यात्रा कर सकेंगे। यूपी सरकार के स्तर पर सोमवार को हुई बैठक में वसंत कुंज से राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक मेट्रो विस्तार परियोजना पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। हालांकि, परियोजना के लिए आवश्यक बजट को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं होने की बात सामने आई है।

एलडीए से फंड की डिमांड

राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रस्तावित एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की लंबाई तीन किलोमीटर से अधिक होने का दावा किया जा रहा है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रारंभिक आकलन के

अनुसार इस हिस्से के निर्माण पर करीब 500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके लिए मेट्रो कॉरपोरेशन ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से वित्तीय सहयोग मांगा है। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल को प्रदेश और देश के प्रमुख पर्यटन एवं प्रेरणात्मक स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

अधिकारियों का दावा है कि मेट्रो कनेक्टिविटी मिलने से बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों, विद्यार्थियों और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सड़क यातायात पर दबाव भी कम होगा। राशि काफी बड़ी होने के कारण एलडीए ने अभी इस पर अंतिम सहमति नहीं दी है।

स्पोर्ट्स कॉरिडोर का निर्माण

राजधानी लखनऊ को विश्वस्तरीय लुक देने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के आसपास गोमती के 7.5 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र को विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए निर्मल गोमती स्पोर्ट्स कॉरिडोर, वाटरफ्रंट रीजुवनेशन और सिटी फॉरेस्ट के विकास की योजना है। यहां पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए भी अलग से ट्रैक का निर्माण किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य गोमती किनारे खेल, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, मनोरंजन एवं व्यावसायिक गतिविधियों का एकीकृत केंद्र विकसित करना है। यूपी एससीआर के तहत इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्तावित योजना के तहत गोमती नदी के किनारे रिवर प्रोमेनेड, इनडोर एवं आउटडोर स्पोर्ट्स एरिना, कम्युनिटी स्पोर्ट्स क्लब और मनोरंजन गतिविधियों के लिए विशेष क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

'आतंकी के बेडरूम का लोकेशन फीड कर देंगे, ब्रह्मोस मिसाइल सीधे खटिया तक पहुंचेगी', लखनऊ में बोले ब्रजेश पाठक

लखनऊ के KGMU के दीक्षांत समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि लखनऊ में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल कंप्यूटर में लक्ष्य फीड करते ही आतंकियों की 'खटिया' तक पहुंचकर सटीक वार करती है।

(जीएनएस)।

लखनऊः किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के 22वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रक्षा क्षेत्र में लखनऊ की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कभी लखनऊ की पहचान सिर्फ 'मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं' से होती थी, लेकिन अब यही शहर देश की सबसे आधुनिक मिसाइलों में शामिल ब्रह्मोस के निर्माण का केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि यह मिसाइल इतनी सटीक है कि कंप्यूटर में लक्ष्य फीड करने के बाद सीधे वहीं जाकर वार करती है और निशाना चूकने का सवाल ही नहीं उठता।

दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने की, जबकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में कुल 1707 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। वहीं 20 विद्यार्थियों को 54 विभिन्न मेडल देकर सम्मानित किया गया।

'लखनऊ में बन रही ब्रह्मोस'

अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सादगी की मिसाल हैं और उनके कंधों पर देश की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी हो रहा है।

पहले लखनऊ के बारे में कहा जाता था- मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। किसी ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि इसी लखनऊ में ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइल बनेगी। यह ऐसी मिसाइल नहीं है कि निशाना लगाकर दागना पड़े। कंप्यूटर में फीड कर देंगे कि किस बेडरूम में कहां आतंकवादी हैं, तो सीधे वहीं जाकर खटिया पर लगेगी। दाएं-बाएं नहीं जाएगी, निशाना चूकने का सवाल ही नहीं है।

ब्रजेश पाठक, उपमुख्यमंत्री

1707 विद्यार्थियों को मिली डिग्री

केजीएमयू के 22वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने की, जबकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में कुल 1707 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। वहीं 20 विद्यार्थियों को 54 विभिन्न मेडल देकर सम्मानित किया गया। एमबीबीएस की छात्रा दीप्ति शर्मा ने सबसे अधिक 16 पदक अपने नाम किए, जिनमें प्रतिष्ठित हीवेट और चांसलर मेडल भी शामिल रहे।

राजनाथ सिंह का बयान

समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी चिकित्सक की असली पहचान केवल उसकी डिग्री या ज्ञान नहीं, बल्कि मरीज के प्रति उसका व्यवहार, संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण होता है। उन्होंने कहा कि मरीज दवा से पहले डॉक्टर के स्नेह और आत्मीयता को याद रखता है, इसलिए इलाज में 'हीलिंग टच' की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

नरोत्तम ने कहा- दतिया में चुनाव प्रचार करूंगा

उन्होंने कहा कि कई मरीज डॉक्टर को सफेद कोट में देखकर ही घबरा जाते हैं, जिसे 'व्हाइट कोट सिंड्रोम' कहा जाता है। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। नए डॉक्टरों से उन्होंने आ'ान किया कि वे सेवा भाव के साथ चिकित्सा पेशे को अपनाएं और हर मरीज के साथ समान व्यवहार करें। उन्होंने यह भी कहा कि मरीज की पूरी बात धैर्य से सुनना चाहिए, क्योंकि कई बार बीमारी का सही सुराग उसी की बातों में छिपा होता है।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का स्वागत करेगा सोनीपत, 800 छात्र बनेंगे इस ऐतिहासिक पल के गवाह

(जीएनएस)।

सोनीपत। देश के परिवहन इतिहास में 17 जुलाई का दिन बेहद खास होने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए चार स्टेशनों पर 800 विद्यार्थी अलग-अलग स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे और हाइड्रोजन ट्रेन की खूबियां जानेंगे।

कार्यक्रम को लेकर सोनीपत जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए उपायुक्त नेहा सिंह ने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की।

प्रशासन का पूरा ध्यान कार्यक्रम को भव्य और तकनीक-अनुकूल बनाने पर है। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा गोहाना, लाठ और मोहाना स्टेशनों पर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं, जहां लोग और विद्यार्थी इस ऐतिहासिक पल का लाइव टेलीकास्ट देख सकेंगे।

डीसी नेहा सिंह ने कार्यक्रम की गंभीरता को देखते हुए गोहाना एसडीएम को गोहाना, खरखौदा एसडीएम को लाठ और गन्नौर एसडीएम को मोहाना स्टेशनों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को खुद मौके पर जाकर निरीक्षण करने और तैयारियों में कोई कमी न छोड़ने के निर्देश दिए हैं।

विद्यार्थियों की रहेगी बड़ी भागीदारी

कार्यक्रम के आयोजन में युवाओं और विद्यार्थियों को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक स्टेशन पर विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे डीक्रस्ट मुरथल, बीपीएस खानपुर कलां, बीपीएल पालिटेक्निक और हिंदू कॉलेज के 200-200 विद्यार्थी सोनीपत, गोहाना, लाठ और मोहाना रेलवे स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे।

जिला प्रशासन ने इन विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित यातायात (रोडवेज बसें), बैठने की व्यवस्था, पेयजल और रिफ्रेशमेंट के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

सुरक्षा व बुनियादी सुविधाओं पर की चर्चा

बैठक में डीसी नेहा सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक रूट प्लान और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा, एसडीएम सोनीपत सुभाष चंद्र, एसडीएम खरखौदा अमित कुमार, पीजीआइ खानपुर के अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र दून, सीटीएम सिमरन, जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया, जीएम रोडवेज संजय कुमार, मोटर वाहन अधिकारी सचिन कुमार तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

पान की दुकान से पेट्रोल-डीजल चोरी तक, कैसे लखनऊ में 36 साल के शख्स ने ड्राइवरों संग मिलकर किया गोरखधंधा?

(जीएनएस)।

लखनऊः दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल संकट के बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में मिलावटी पेट्रोल बेंचने वाले गैंग का पदार्फाश हुआ है।

यह पूरा गोरखधंधा एक पान की दुकान से चलाया जा रहा था। पुलिस ने 36 साल के अनिल सिंह को इस गिरोह का मास्टरमाइंड बताया है। दावा है कि उसने अपनी पान की दुकान का इस्तेमाल करके एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो बाद में फ्यूल चोरी के एक संगठित सिंडिकेट में बदल गया। पान की इस दुकान पर फ्यूल टैंकर ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर अक्सर आते-जाते रहते थे।

मलिहाबाद के संन्यासी बाग इलाके में इस रैकेट का खुलासा एडिशनल DCP (क्राइम) किरण यादव की अगुवाई में छापेमारी के दौरान हुआ। इस दौरान हरदोई के रहने वाले चार आरोपियों अनिल सिंह, अभिषेक

राजपूत (25), धीरज सिंह (33) और रामतीर्थ (35) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 7,750 लीटर पेट्रोल, 4,000 लीटर डीजल, 1,150 लीटर मिलावटी पेट्रोल और 3,200 लीटर इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जब्त किया। फ्यूल निकालने और मिलावट के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं।

छह महीने से चल रहा था रैकेट

अऊढ किरण यादव ने बताया कि अनिल करीब छह महीने से यह रैकेट चला रहा था। अनिल ने सबसे पहले उन टैंकर ड्राइवरों से दोस्ती की जो चाय, सिगरेट पीने के लिए उसकी दुकान पर रुकते थे। कई महीनों तक उनका भरोसा जीतने के बाद उसने उन्हें एक्स्ट्रा पैसे कमाने के आसान तरीके के तौर पर फ्यूल चोरी का आइडिया दिया।

ड्राइवरों को मिलता था कमीशन

पुलिस ने बताया कि ड्राइवरों से पेट्रोल या डीजल की हर सफल हेराफेरी के लिए कमीशन का वादा किया गया था। पकड़े जाने के डर को दूर करने के लिए अनिल ने दावा किया कि उसके पास ऐसे सॉल्वेंट और केमिकल हैं जिनसे टैंकर से निकाले गए फ्यूल की मात्रा की भरपाई की जा सकती है।

शुरूआत में केवल 5 से 6 लीटर फ्यूल चुराते थे

शुरूआत में कम मात्रा में फ्यूल चोरी किया जाता था। हर टैंकर से सिर्फ 5-6 लीटर ताकि शक न हो। बाद में फ्यूल की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ती गई, जिससे एक छोटे स्तर का ऑपरेशन एक संगठित नेटवर्क में बदल गया जिसमें कई लोग शामिल थे और सबकी भूमिकाएं तय थीं।

मुरार नगर में झाड़ियों से घिरा मुख्य मार्ग बना हादसों का कारण

समाजसेवी व अधिवक्ता विवेक मिश्रा (विराट) ने बीडीओ से की सफाई की मांग।

(जीएनएस)।

विकासखंड संडीला की ग्राम पंचायत सोम के मुरार नगर में मुख्य खड़ंजा मार्ग के दोनों ओर उगी झाड़ियों और घास-फूस से ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इस गंभीर समस्या को लेकर ग्राम पंचायत सोम निवासी समाजसेवी एवं अधिवक्ता विवेक मिश्रा (विराट) ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को प्रार्थना पत्र सौंपकर तत्काल

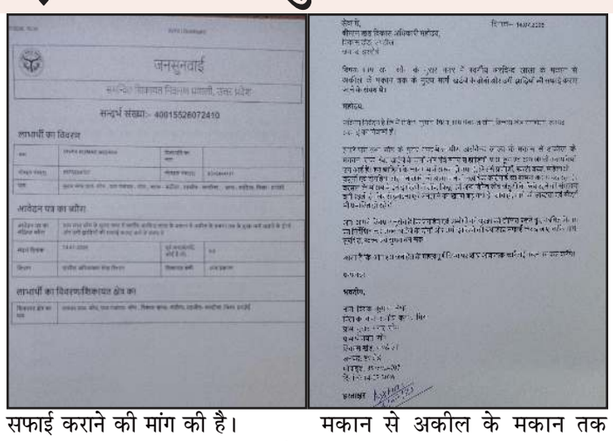

सफाई कराने की मांग की है।

प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि स्वर्गीय अरविंद लाला के मकान से अकील के मकान तक जाने वाले मुख्य मार्ग के दोनों ओर लंबे समय से झाड़ियां और जंगली वनस्पतियां उगी हुई हैं। इससे सड़क संकरी हो गई है और राहगीरों, स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों तथा दोपहिया वाहन चालकों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

विवेक मिश्रा (विराट) ने कहा कि बरसात के मौसम में इन झाड़ियों में सांप, बिच्छू सहित अन्य विषैले जीव-जंतुओं के छिपे रहने की आशंका बनी रहती है, जिससे दुर्घटना और जनहानि का खतरा भी बढ़ गया है। इसके अलावा

पिपरा मुजफ्ता में कृषक गोष्ठी, बीमा और सहफसली से आय बढ़ाने पर जोर, 'उन्नति खेती, खुशहाल किसान' का दिया गया संदेश

(जीएनएस)।

पीलीभीत/पूरनपुर।सहकारी गन्ना विकास समिति पूरनपुर के तत्वावधान में विकास खंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत पिपरा मुजफ्ता में मंगलवार को विशाल कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

गोष्ठी में सचिव मनीष कुमार सिंह, सहकारी गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष नितिन दीक्षित एवं बलरामपुर चीनी मिल के प्रतिनिधि आशुतोष द्विवेदी ने किसानों को वैज्ञानिक खेती के साथ-साथ सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी।

//गन्ने की सहफसली बुवाई// विशेषज्ञों ने बताया कि गन्ने के साथ दलहन, तिलहन और सब्जी जैसी फसलें लेने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और भूमि की उर्वरकता भी बनी रहेगी।

/खरपतवार नियंत्रण//समय पर खरपतवार नियंत्रण के तरीके बताए गए। दवाओं के उचित प्रयोग, खुराक और समय पर निराई-गुड़ाई के बारे में जानकारी दीं ।

//गन्ना बंधाई एवं लाल सड़न रोग पर चर्चा// बलरामपुर चीनी मिल के प्रतिनिधि आशुतोष द्विवेदी ने गन्ना किसानों से अपील करते हुए कहां कि किसान अपने गन्ने की बंधाई अवश्य करें इससे किसान भाइयों को अत्यधिक फायदा होगा एवं गन्ना

वैरायटी 038 सहित कई अन्य वैरायटी जिसमें लाल सड़न' की समस्या आती है वह किसान अपने खेत में अभी से ही प्रारंभिक इलाज शुरू कर दें लाल सड़न रोग को नियंत्रण करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करें बलरामपुर चीनी मिल के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर फ्री में दिया जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर डालने की पूरी विधिः बताई एवं किसानों को जागरूक किया।

गन्ने की उन्नत किस्मों, संतुलित उर्वरक प्रयोग, ड्रिप सिंचाई और मृदा परीक्षण के महत्व पर चर्चा की गई।

//फसल बीमा योजना// किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। सचिव ने कहा कि प्राकृतिक आपदा, कीट और बीमारी से फसल को होने वाले नुकसान पर बीमा कंपनी मुआवजा देती है। समय सीमा के अंदर प्रीमियम जमा कराकर सभी किसान बीमा अवश्य कराएं।

इस अवसर पर सचिव मनीष कुमार सिंह ने कहा कि विभाग किसानों को हर संभव मदद देगा। गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष नितिन दिक्षित ने कहा कि किसी भी समस्या के लिए किसान सीधे समिति कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसानों की समस्या का तत्काल निस्तारण किया जाएगा।

आशुतोष द्विवेदी ने मिल द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं, समय से गन्ना पर्ची और भुगतान की जानकारी दी।

गोष्ठी में बड़ी संख्या में गन्ना किसान मौजूद रहे। किसानों ने विशेषज्ञों से बीमा, ऋण और नई किस्मों को लेकर सवाल भी पूछे।

केजीएमयू हॉस्टल में नॉनवेज पर रोक, लखनऊ से उठा नया विवाद, सपा-कांग्रेस ने सरकार को घेरा

(जीएनएस)।

नॉनवेज भोजन बंद करने के मामले पर अब राजनीति में शुरू हो गई है. सपा और कांग्रेस ने इसे मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने और भेद पैदा करने वाला बताया है. छात्रों ने इसे समानता के अधिकार के विपरीत बताया है

उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नॉनवेज भोजन बंद करने के फैसले से नया विवाद खड़ा हो गया है. यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अब हॉस्टल में शाकाहारी भोजन ही परोसा जाने का निर्देश दिया है. जिसके बाद कुछ छात्रों ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे समानता के अधिकार के विपरीत बताया है.

इस मामले पर अब राजनीति में शुरू हो गयी है. सपा और कांग्रेस ने इसे मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने और भेद पैदा करने वाला बताया है. जबकि प्रबंधन का दावा है कि छात्रों की सेहत के हिसाब से बेहतर खाना दिया जा रहा है.

वीसी के निर्देश पर बदला मेन्यू

जानकारी के मुताबिक डब्ल्यू के वीसी के निर्देश पर छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं के लिए अब शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा. जबकि कई छात्रों ने इस पर ऐतराज जताया है. केजीएमयू परिसर के सी. वी. छात्रावास में जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची, तब यहां पर शाकाहारी भोजन करते छात्र मिले. स्टाफ कुछ भी बोलने से बचता रहा, लेकिन जानकारी मिली कि सप्ताह में एक दिन अंडा करी डिमांड पर बन जाती थी. लेकिन अब पूरी तरह से शाकाहारी भोजन मिलेगा और जिसे खाना है बाहर जाकर खाए.

छात्रों की सेहत का ध्यान का दावा

सी. वी. छात्रावास के प्रभारी एस. एन. सिंह ने बताया कि अब पूरी तरह से नया मेन्यू तैयार कर रहे हैं, जिसमें प्रोटीन और डाइट का ध्यान रखा जा रहा है. छात्रों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.जबकि कुछ ने इसे बेहतर बताया तो कुछ छात्रों ने कहा कि ये समानता का व्यवहार नहीं है जिसकी इच्छा हो उसके लिए नॉनवेज की व्यवस्था भी होनी चाहिए.

सपा-कांग्रेस ने उठाए सवाल

मामले के सामने आने के बाद राजनीति भी इस पर गर्म हो गयी है. विपक्षी दल इस पर निशाना साध रहे हैं. कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने कहा कि KGMU की समस्याओं पर बात नहीं करते खाने पीने की चीजों पर कुठाराघात करते हैं. उधर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बताया. उन्होंने कहा कि जब विकास की बात पर फेल हो जाते हैं तब इस तरह की बात करते हैं. बंगाल में प्रदर्शन कर रहे थे, हेमंत विश्वशर्मा क्या बोल रहे थे ? अब ये भेद पैदा करना चाहते हैं.

लखनऊ में शहीद पथ पर बनेगा 23 किमी. लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा

(जीएनएस)।

लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए शहीद पथ पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साकार होने जा रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कहने पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ एयरपोर्ट से आउटर रिंग रोड तक लगभग 23 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं. नितिन गडकरी ने कहा कि इस वर्ष दिसंबर तक भूमि पूजन कर परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा. दोनों वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने योगी सरकार की कार्यशैली की खुलकर सराहना की.

सोमवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4,850 करोड़ रुपये से अधिक की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया.

शहीदपथ पर वाहन चालकों को जाम से मिलेगी राहत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र सरकार थी, तब उनके सड़क परिवहन मंत्री रहते हुए शहीद पथ का शिलान्यास हुआ था. आज यही शहीद पथ लखनऊ की लाइफलाइन बन चुका है. लगातार बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अब इसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनाना समय की आवश्यकता है, जिससे वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में इसी कॉरिडोर पर मेट्रो भी संचालित की जाए, ताकि लोगों को तेज और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो सके.

तीन लेयर फ्लाईओवर बनेगा दुनिया के आकर्षण का केंद्र

नितिन गडकरी ने कहा कि लखनऊ में प्रस्तावित तीन लेयर

एलिवेटेड फ्लाईओवर विश्व स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनेगा. इस परियोजना में आधुनिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे सड़क और सार्वजनिक परिवहन दोनों को मजबूती मिलेगी. किसी भी राज्य के विकास की नींव मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होती है. पानी, बिजली, परिवहन और संचार व्यवस्था बेहतर होने से उद्योग, व्यापार और निवेश बढ़ता है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और गरीबी व बेरोजगारी कम होती है.

लखनऊ-सीतापुर सिक्स लेन हाईवे सहित कई परियोजनाओं को मिली मंजूरी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि लखनऊ से सीतापुर तक प्रस्तावित छह लेन राजमार्ग को भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तत्काल स्वीकृति दे दी है और जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू होने की उम्मीद है. वहीं नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 50 से 60 हजार करोड़ रुपये की नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. अगले दो वर्षों में प्रदेश में लगभग पांच लाख करोड़ रुपये के विकास कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है. नितिन गडकरी ने कहा कि लखनऊ के किसान पथ पर सर्विस रोड बनाई जाएगी. इसके अलावा अयोध्या-गोंडा बाईपास, आनंदनगर-महराजगंज बाईपास, पडरौना-तमकुही बाईपास तथा दादरी-लालकुआं छह लेन एलिवेटेड रोड जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है.

रक्षा मंत्री और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी की सराहना की

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास पूरे देश में चर्चा का विषय है. किसी भी प्रदेश के विकास की पहली शर्त मजबूत कानून व्यवस्था होती है और योगी सरकार ने यह स्थापित करके दिखाया है. लखनऊ के विकास से जुड़े हर प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया और आने वाले समय में लखनऊ के आसपास बड़े उद्योग स्थापित होंगे.

यूपी में सीएम योगी ने समाप्त किया गुंडाराजः नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत कर लोगों का विश्वास जीता और गुंडाराज को समाप्त किया. किसी भी देश और राज्य के विकास में चार बातें महत्वपूर्ण होती हैं. सबसे पहली आवश्यकता मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर के चार प्रमुख आधार हैं वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जहां ये चारों व्यवस्थाएं मजबूत होती हैं, वहां व्यापार, उद्योग और कारोबार तेजी से बढ़ते हैं. इसके साथ ही पूंजी निवेश आता है. जहां व्यापार, उद्योग और निवेश बढ़ता है, वहां रोजगार का सृजन होता है और जहां रोजगार का निर्माण होता है, वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी स्वतः दूर हो जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है.

स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सक्रिय

(जीएनएस)।

हरदोई/संडीला लखनऊ-हरदोई हाईवे पर स्थित संडीला लायंस पब्लिक स्कूल के सामने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर वी बी न्यूज द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित खबर का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया।

मंगलवार को यातायात प्रभारी अनिल सैनी पुलिस बल के साथ स्कूल पहुंचे और सड़क की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं

तथा भरोसा दिलाया कि बच्चों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि स्कूल खुलने और छुट्टी के समय यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा तथा आवश्यक सुरक्षा उपाय जल्द लागू किए जाएंगे।

स्थानीय लोगों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन ने वी न्यूज द्वारा इस जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। उनका कहना है कि इन कदमों से स्कूली बच्चों का आवागमन पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हो सकेगा।

लोगों व अभिभावकों ने सख्त कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्राधिकारी (सीओ) संतोष कुमार को धन्यवाद दिया व आभार प्रकट किया।

किसानों की आवाज बनकर उभरे इंजीनियर संचित दीक्षित, समाजसेवा में निभा रहे अग्रणी भूमिका

संवाददाता रोहित मिश्रा

पीलीभीत/बीसलपुर भारतीय किसान यूनियन (भानु) के वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष (बरेली मंडल) एवं एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, पीलीभीत के जिला निदेशक इंजीनियर संचित दीक्षित किसानों के हितों की रक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के कारण क्षेत्र में एक सक्रिय जनसेवक के रूप में पहचान बना रहे हैं।

इंजीनियर संचित दीक्षित लगातार किसानों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं। बिजली विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, तहसील और ब्लॉक स्तर पर किसानों एवं आम नागरिकों की शिकायतों को प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उनका मानना है कि किसानों और गरीबों को समय पर न्याय मिलना लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

संगठन के विस्तार और कार्यकताओं के मार्गदर्शन में भी संचित दीक्षित सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे समय-समय पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं, जनहित के मुद्दों और संगठन की भावी रणनीति पर चर्चा करते हैं।

उनके प्रयासों से संगठन का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और अधिक लोग किसान हितों की लड़ाई से जुड़ रहे हैं।

एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जिला निदेशक के रूप में भी इंजीनियर संचित दीक्षित भ्रष्टाचार के मामलों को संबंधित विभागों तक पहुंचाने, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करने और जनजागरूकता अभियान चलाने में सक्रिय रहते हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानूनी एवं लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करना समाज और किसानों के हित में आवश्यक है।

संगठन के कार्यकताओं का कहना है कि संचित दीक्षित एक मेहनती, कर्मठ और जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो हर परिस्थिति में किसानों और आम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। समाजसेवा, जनहित और किसान कल्याण के कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी उन्हें क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक कार्यकताओं में शामिल करती है।

क्षेत्र के लोगों का मानना है कि किसानों के हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, समाजसेवा के प्रति समर्पण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी सक्रिय भूमिका उन्हें एक प्रभावी जननेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित कर रही है। कई किसानों की समस्याएं उनके प्रयासों से संबंधित विभागों तक पहुंचीं और अनेक मामलों में समाधान भी सुनिश्चित हुआ। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी किसानों के अधिकारों की रक्षा, गरीबों को न्याय दिलाने और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष लगातार जारी रहेगा।